www.tamsasanket.com
वर्ष: 05 || अंक 341 || लखनऊ
बुधवार
18 मार्च 2026 || पृष्ठ: 04 || मूल्य: ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
https://epaper.tamsasanket.com

दैनिक तमसा संकेत

डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र
लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित

मौसम
सूर्योदय: 06:11
सूर्यास्त: 06:17
अधिकतम: 34°00
न्यूनतम: 20°00

पेज 03

विशेष समाचार | अफगानिस्तान और पाकिस्तान... >> पेज 02 | लखनऊ से मोबाइल चुराकर... >> पेज 04 | संजय दत्त-नोरा का गाना सरके...

भाजपा नेता ने पिछली बार नंदीग्राम में सीएम को हराया था, इस बार भबानीपुर में मुकाबला, टीएमसी की लिस्ट जारी

बंगाल में फिर ममता-सुवेंदु भिड़ेंगे

ऐलान

तमसा संकेत, एजेंसी

कोलकाता/चेन्नई। तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की कुल 294 सीटों में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बाकी 3 सीटें सहयोगी बीजीपीएम को दी हैं। ममता बनर्जी भबानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। उनका मुकाबला भाजपा नेता सुवेंद्र अधिकारी से होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने कहा कि मैं BJP से कहना चाहती हूं कि आप डर क्यों रहे हैं। अगर लड़ना है तो गैस संकट पैदा मत कीजिए। मैदान में आकर सही तरीके से मुकाबला कीजिए।

चुनाव आयोग ने शानदार खेल दिखाया- ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता में कहा, उम्मीदवारों की सूची घोषित करने से पहले, मैं बंगाल की जनता का धन्यवाद करती हूं। मैं 'मां माटी मानुष बंग्लार संस्कृति' सभी को समर्पित करती हूं और 294 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी करती हूं। मैं भाजपा से कहना चाहती हूं - आप क्यों डर रहे हैं? अगर चुनाव लड़ना है तो गैस संकट पैदा मत कीजिए; सही तरीके से मैदान में उतरिए। चुनाव आयोग ने शानदार खेल दिखाया। भाजपा के पास कोई मौका नहीं है। इस बार आपकी सीटें पिछली बार के मुकाबले कम होंगी। यह पश्चिम बंगाल के अस्तित्व की लड़ाई है। बंगाल जीतेगा। 'दिल्ली का लड्डू' नहीं जीतेगा।

4 राज्यों में एसआईआर, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा नाम कटे

जिन पांच राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें SIR के बाद तमिलनाडु से सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि 27 अक्टूबर 2025 को SIR प्रक्रिया शुरू होने के दौरान राज्य में कुल 6,41,14,587 वोटर थे। करीब चार महीने चली SIR में 74,07,207 लोगों के नाम हटाए गए हैं।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एमडीएमके का घोषणापत्र जारी

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके की सहयोगी एमडीएमके ने मंगलवार को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। घोषणापत्र में राज्य स्वायत्तता, मछुआरों का कल्याण, राज्यपाल पद का उन्मूलन, स्टरलाइट तांबा संयंत्र का स्थायी बंद होना और बाल विवाह का पूर्ण उन्मूलन सहित कई क्षेत्रीय और सामाजिक मुद्दे शामिल किए गए हैं। घोषणापत्र जारी करते हुए एमडीएमके के संस्थापक वाइको ने कहा कि एक समर्पित समिति ने तीन महीने तक पूरे राज्य का दौरा किया।

‘उद्योग’ की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

तय होगा सरकारी विभाग-एनजीओ उद्योग माने जाएंगे या नहीं

फैसला

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में ‘उद्योग’ शब्द की परिभाषा से जुड़े मामले पर सुनवाई शुरू की। कोर्ट तय करेगा कि सरकारी विभाग, अस्पताल, स्कूल और NGO जैसी संस्थाएं ‘उद्योग’ की कैटेगरी में आएंगी या नहीं और उन पर श्रम कानून लागू होंगे या नहीं। मंगलवार को मामले की सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान पक्षकारों ने 1978 के बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा फैसले में दी गई ‘उद्योग’ की परिभाषा पर शुरुआती दलीलें रखीं। सुनवाई 18 मार्च को खत्म हो जाएगी। बेंच ने इस बात पर विचार शुरू किया कि क्या उस फैसले में दी गई व्यापक परिभाषा सही है या उसके दायरे को सीमित करने की जरूरत है। मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। बेंच की अध्यक्षता CJI सूर्यकांत कर रहे है।

>> (शेष पेज 04 पर)

चुनाव आयोग ने 1,100 से अधिक पर्यवेक्षकों की तैनाती की

चुनाव आयोग (ईसी) ने अगले महीने होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों और विधानसभा उपचुनावों के लिए 1,111 पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभाओं के चुनाव होने के साथ-साथ, कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव भी अप्रैल में होने हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि पर्यवेक्षक ईसी की आंख और कान के रूप में काम करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हों। ईसी ने निर्देश दिया है कि पर्यवेक्षक गुरुवार तक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच जाएं। ईसी ने कहा कि पहुंचने पर, पर्यवेक्षक अपने संपर्क विवरण सार्वजनिक करेंगे और उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों या उनके प्रतिनिधियों, या जनता के किसी भी सदस्य से चुनाव संबंधी शिकायतों को सुनने के लिए प्रतिदिन एक निश्चित समय निर्धारित करेंगे।

रजनीकांत का टीवीके को जवाब- समय बोलता नहीं, बल्कि जवाब देता है

सुपरस्टार रजनीकांत ने मंगलवार को टीवीके के महासचिव आदव अर्जुन की उनके बारे में की गई “अपमानजनक टिप्पणियों” की निंदा की। रजनीकांत ने कहा कि समय ही जवाब देगा। X पर पोस्ट किए गए एक आधिकारिक संदेश में, अभिनेता ने अर्जुन की टिप्पणियों पर चिंता व्यक्त की और उन्हें “सत्य के विपरीत” बताया। उन्होंने उन राजनीतिक नेताओं, प्रशंसकों और मीडिया सदस्यों के प्रति आभार भी व्यक्त किया जिन्होंने “अपमानजनक” टिप्पणियों की आलोचना की। तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) पार्टी में नेतृत्व की भूमिका निभाने वाले आधव अर्जुन ने हाल ही में मेरे बारे में एक ऐसी राय व्यक्त की जो सत्य के विपरीत थी। मैं तमिलनाडु विधानसभा के माननीय विपक्ष नेता श्री एडप्पाडी के. पलानीस्वामी, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन, केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन, तमिलनाडु के मंत्रियों मीडिया के सदस्यों और मेरे प्रिय प्रशंसकों (जिन्हें मैं भगवान मानता हूँ) का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं अपने प्रियजनों को उनके अपमानजनक बयानों की निंदा करने और मेरे समर्थन में आवाज उठाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

> ईसी ने कहा कि पहुंचने पर, पर्यवेक्षक अपने संपर्क विवरण सार्वजनिक करेंगे और उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों या उनके प्रतिनिधियों, या जनता के किसी भी सदस्य से चुनाव संबंधी शिकायतों को सुनने के लिए प्रतिदिन एक निश्चित समय निर्धारित करेंगे। यह जोड़ी है वरिष्ठ नेता पी. सी. जॉर्ज और उनके बेटे शोन जॉर्ज की। पीसी जॉर्ज को पूनजार से उम्मीदवार बनाया गया है। शोन जॉर्ज को पाला सीट से मैदान में उतारा गया है।

पश्चिम बंगाल- 3 बार से ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री

14 साल से CM ममता के सामने BJP मुख्य चुनौती है। 2026 के चुनाव में टीएमसी जीती तो ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। वे ऐसा करने वाली देश पहली महिला होंगी। जयललिता के नाम 5 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। हालांकि, वह 1991 से 2016 तक अलग-अलग कार्यकाल (लगातार नहीं) में मुख्यमंत्री पद पर रहीं।पश्चिम बंगाल- 3 बार से ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री 14 साल से CM ममता के सामने BJP मुख्य चुनौती है। 2026 के चुनाव में टीएमसी जीती तो ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। वे ऐसा करने वाली देश पहली महिला होंगी। जयललिता के नाम 5 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। हालांकि, वह 1991 से 2016 तक अलग-अलग कार्यकाल (लगातार नहीं) में मुख्यमंत्री पद पर रहीं।

केरल चुनाव: एनडीए ने ईसाई बहुल सीटों पर पिता-पुत्र को उतारा मैदान में

केरल विधानसभा चुनाव (9 अप्रैल) से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। NDA ने कोट्टायम जिले की दो ईसाई बहुल सीटों पूनजार और पालासे पिता-पुत्र की जोड़ी को उम्मीदवार बनाया है। हालिया फेरबदल में 12 जिलों के SP भी बदले गए हैं।ईसी ने निर्देश दिया है कि पर्यवेक्षक गुरुवार तक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच जाएं।

यूपी में फिर बिगड़ेगा मौसम, 4 दिन बारिश का अलर्ट

बिजली भी गिर सकती है, 48 घंटे में 3 डिग्री सेल्सियस लुढ़का पारा

आशंका

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। यूपी में मौसम फिर बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने 19 मार्च से 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तेज आंधी के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। वहीं, पिछले 48 घंटों में जगह-जगह हुई बारिश की वजह से तापमान करीब 3°C तक लुढ़क गया है। इससे रात और सुबह के वक्त ठंड का एहसास हो रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हुई। शामली में एक-दो जगहों पर ओले भी गिरे। पूर्वी यूपी में भी कहीं-कहीं बौछारें पड़ीं। कहीं-कहीं आंधी भी चली। इस वजह से तापमान में गिरावट देखी गई। पारा 40°C से नीचे आ गया। सबसे ज्यादा तापमान सुल्तानपुर में रिकॉर्ड किया गया। यहां अधिकतम तापमान 37.4°C दर्ज किया गया।

> यूपी में पिछले 2 दिन हल्की बारिश हुई। इस दौरान पारे में गिरावट आई। लोगों को कुछ हद तक गर्मी से राहत मिली।

>> (शेष पेज 04 पर)

फास्ट न्यूज

ईरान-इजराइल युद्ध में राजस्थान के एक और युवक की मौत

खंडेला (सीकर)। ईरान-अमेरिका, इजराइल युद्ध में राजस्थान के एक और बेटे की मौत हो गई। ओमान में हुए ड्रोन हमले का शिकार सीकर जिले के विक्रम वर्मा (22) हुए हैं। वह खंडेला के अगलोई गांव के रहने वाले थे। यह घटना 14 मार्च की है। आज (मंगलवार) शव गांव पहुंचा। गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। मौत से एक दिन पहले ही उन्होंने अपने परिवार वालों से ग्रुप वीडियो कॉल पर बात की थी।

बच्चा गोद लेने पर मां को 12 हफ्ते छुट्टी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अब किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला को 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। सिर्फ 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर ही छुट्टी देना गलत है। जस्टिस जे बी परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान बेंच ने धारा 60(4) को असंवैधानिक करार देते हुए बच्चे की उम्र 3 महीने से कम होने के नियम को रद्द कर दिया। हमसानंदिनी नंदूरी ने इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि उम्र के आधार पर छुट्टी देना गलत है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन है।

रील बना रहे युवक ने खुद पर गोली चलाई

नई दिल्ली। दिल्ली के न्यू अशोका गार्डन में मंगलवार को रील बनाते वक्त एक युवक की मौत हो गई। वह अपने दोस्त की पिस्तौल लेकर रील बना रहा था। दोस्त ही इसे शूट कर रहा था। पुलिस का कहना है पिस्तौल का लाइसेंस वीडियो शूट करने वाले दोस्त के नाम पर है। मामले की जांच की जा रही है। वीडियो के शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा है। रील बना रहा युवक

एयरपोर्ट पर 8.55 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी

17 वैक्यूम पॉलीबैग में मस्कट से लखनऊ लेकर आया

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ एयरपोर्ट पर मस्कट से आए एक यात्री के पास से 8.55 करोड़ का गांजा (हाइड्रोपोनिक वीड) पकड़ा गया। आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीमा शुल्क अधिकारियों के अनुसार, सोमवार को ओमान एयर की उड़ान (डब्ल्यूवाई 265) से लखनऊ पहुंचे एक संदिग्ध यात्री के सामान की जांच के दौरान गांजा मिला। खुफिया इनपुट के आधार पर उसके बैग की तलाशी ली गई, जिसमें प्रतिबंधित पदार्थ छिपाकर रखा गया था। जांच के दौरान यात्री के काले-भूरे रंग के बैकपैक से 17 वैक्यूम पॉलीबैग मिले। इन पैकेटों को कैमलिन कार्बन पेपर में लपेटकर छिपाया गया था। पैकेटों में हरे

रंग का पदार्थ पाया गया, जिसके हाइड्रोपोनिक वीड होने की आशंका है। बरामद पदार्थ का कुल वजन 8.552 किलोग्राम है। सीमा शुल्क विभाग ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस गांजे की अनुमानित कीमत 8,55,20,000 रुपए आंकी गई। बरामदगी के बाद मादक पदार्थ को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 के तहत जब्त कर लिया गया।

वेयरहाउस में भी आग लगी, इजराइल बोला- ईरान के सिक्योरिटी चीफ लारीजानी को मारा

दावा : यूएई के शारजाह में जहाज पर ईरान का हमला

विस्फोट

तमसा संकेत, एजेंसी

तेल अवीव/तेहरान। ईरानी मीडिया के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में एक जहाज पर ईरान ने हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को शारजाह पोर्ट पर एक जहाज में जोरदार विस्फोट हुआ। वहीं शारजाह के सिक्स्थ इंडस्ट्रियल एरिया में एक वेयरहाउस में भी आग लग गई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार दमकल टीमों ने करीब 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया और किसी के

घायल होने की सूचना नहीं है। इस बीच इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी को मार गिराया है। हालांकि इस दावे की ईरान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, इजराइल के दावों के बीच लारीजानी के X अकाउंट पर एक हाथ से लिखा नोट पब्लिश किया है। इसमें उन्होंने हमले में मारे गए ईरानी नौसैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है, जिनका अंतिम संस्कार आज होने की उम्मीद थी। भारत का नंदा देवी जहाज होर्मुज स्ट्रेट को पार करके आज रात 2:30 बजे गुजरात के वडिनार पोर्ट पहुंचा। इस जहाज में करीब 46,500 मीट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) लाई गई है। इससे पहले भारतीय जहाज शिवालिक सोमवार को LPG लेकर ‘मुंद्रा पोर्ट’ पहुंच चुका है। इस जहाज पर करीब 46 हजार मीट्रिक टन LPG है, जो लगभग 32.4 लाख घरेलू गैस सिलेंडरों के बराबर है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि उनका देश ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में अपने सैनिक नहीं भेजेगा।

>> (शेष पेज 04 पर)

- इजराइली एयर डिफेंस सिस्टम ने सोमवार रात ईरानी से आ रही एक मिसाइल को बीच में ही रोक दिया।
- अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोमवार को ईरानी हथियारों पर हमले का फुटेज जारी किया।

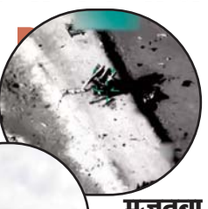

दावा-इजराइली हमले में बजीस फोर्स के 300 सैनिकों की मौत

तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइली सेना के रातभर हुए हमलों में ईरान की बसीज फोर्स को बड़ा नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि करीब 300 कमांडर और फील्ड अधिकारी मारे गए हैं। ये हमले बसिज के अहम कमांड सेंटर और ऑपरेशन चलाने वाले ठिकानों पर किए गए। बसिज वही फोर्स है जिसे अक्सर सरकार विरोधी प्रदर्शन और विरोध को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

मुजतबा खामेनेई बोले- पहले अमेरिका-इजराइल से हिसाब, फिर शांति बात

ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई ने शांति की कोशिशों को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक, दो देशों के जरिए विदेश मंत्रालय तक भेजे गए प्रस्तावों को उन्होंने खारिज कर दिया और विदेश नीति की एक बैठक में कहा कि अभी “शांति का सही समय नहीं है।”

रोक : स्पीकर बिरला ने सांसदों से कहा- पोस्टर और एआई से बनीं तस्वीरें न दिखाएं

लोकसभा से 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन हटा

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को पहले फेज के दौरान निलंबित किए गए 8 सांसदों पर लगा सस्पेंशन हटा दिया गया। इनमें कांग्रेस के 7 और लेफ्ट के एक सांसद हैं। ये आठ सांसद 4 फरवरी को लोकसभा से पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किए गए थे। उन पर हंगामा करने के दौरान स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी की कुर्सी की ओर कागज फेंकने का आरोप लगा था। यह हंगामा उस समय हुआ था जब राहुल गांधी सदन में पूर्वी लद्दाख में 2020 के भारत-चीन सीमा तनाव का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस सांसद के. सुरेश समेत 3 सांसदों ने सस्पेंशन प्रस्ताव रखा। इसके बाद ध्वनि मत से इसे पास कर दिया गया। इससे पहले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने इसका समर्थन किया। धर्मेंद यादव ने कहा कि सदन की मर्यादा में सत्ता पक्ष को भी मान रखना होगा।

>> (शेष पेज 04 पर)

> सरकारी सूत्रों ने बताया कि विपक्ष को साथ लेने के लिए उनसे संपर्क साधा गया है, ताकि संसद में संविधान संशोधन विधेयक को आसानी से पारित कराया जा सके।

शिवराज चौहान ने कहा- कांग्रेस ने सिर्फ वोट-बैंक की राजनीति की

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा, 'कुछ कांग्रेस शासित राज्यों को योजनाओं में ‘PM’ नाम पसंद नहीं है, इसलिए 1,93,000 घरों को मंजूरी नहीं दी गई।' उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत देश के गरीब परिवारों को इलाज देता है। कांग्रेस ने कभी गरीबी खत्म नहीं की। आपने किसकी गरीबी दूर की।

बीजेपी सांसद गुलाम अली ने कहा- कांग्रेस देश विरोधियों के साथ खड़ी

बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली ने शून्यकाल के दौरान एलपीजी शॉर्टेज के मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष को घेरा। उन्होंने क्रूड ऑयल, एलपीजी रिजर्व के आंकड़े गिनाते हुए कहा कि हमने पर्याप्त जखीरा रखा है। कांग्रेस हमेशा देश विरोधियों के साथ खड़ी हुई है।

कांग्रेस सांसद ने कहा- 8 सांसदों का निलंबन वापस होगा

सांसदों का निलंबन रद्द किए जाने पर कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा, स्पीकर ने कुछ निर्देश दिए हैं और संसदीय कार्य मंत्री ने भी सदन की मर्यादा और अनुशासन का जिक्र किया। अब यह निर्णय लिया गया है कि निलंबित सदस्यों का निलंबन आज ही वापस लिया जाएगा।

कांग्रेस ने ओडिशा में 3 विधायकों को पार्टी से निकाला

भुवनेश्वर, चंडीगढ़। ओडिशा में कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले तीन विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी ने तीनों विधायकों को विधानसभा से अयोग्य घोषित करने के लिए स्पीकर को लेटर भी लिखा है। हरियाणा में कांग्रेस पांच विधायकों को नोटिस देने की तैयारी कर रही है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने पार्टी छोड़ दी है। ओडिशा में कांग्रेस ने रमेश जेना, दशरथी गोमांगो और सोफिया फिरदौस को पार्टी से निकाला है। तीनों विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय के पक्ष में वोट दिया था। क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस और BJD के संयुक्त उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल, दोनों राज्यों में कांग्रेस के कुल 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। 16 मार्च को 11 सीटों पर हुए चुनाव में 9 सीटें एनडीए के खाते में गईं। इससे पहले 10 राज्यों की 37 सीटों में से 26 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे।

उत्तराखंड के बाद गुजरात में यूसीसी की तैयारी

समिति ने सीएम भूपेंद्र पटेल को रिपोर्ट सौंपी

चर्चा

तमसा संकेत, एजेंसी

गांधीनगर। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो सकता है। यूसीसी के लिए गठित समिति ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत अध्ययन के बाद इसने अंतिम सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट पेश की है। गुजरात सरकार आज शाम को इस रिपोर्ट पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा करेगी। यूसीसी से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा मौजूदा विधानसभा सत्र में ही की जाएगी। रिपोर्ट 23 मार्च को सदन में रखी जा सकती है, जबकि 24 मार्च को बिल पेश किए जाने की संभावना है, जो इस बजट सत्र का अंतिम दिन भी है। अगर यह बिल पास हो जाता है, उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने X पर लिखा- गुजरात में समान नागरिक संहिता (UCC) के क्रियान्वयन के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने अपनी विस्तृत दी है।

सम्पादकीय

पांच राज्यों में चुनाव, कई सवाल

देश में एक बार फिर चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस वार्ता में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। चुनाव अगले महीने 9 तारीख से शुरु होकर 29 अप्रैल तक चलेंगे। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान होगा, जबकि सभी राज्यों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। जिस तरह महीने भर का चुनाव कार्यक्रम बनाया गया है, उसके बाद एक देश एक चुनाव जैसी बातें बेमानी ही लगती हैं। पिछले साल के चुनावों के वक्त भी ऐसा ही हुआ था और उससे पहले भी परिदृश्य ऐसा ही था कि कई चरणों में लंबी चुनावी प्रक्रिया चलती है। अगर स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनावों के लिए यह लंबी प्रक्रिया जरूरी है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर फिर एक देश एक चुनाव के लिए जनता के पैसों पर समिति बनाकर उसमें सेवानिवृत्त लोगों को भरने का क्या औचित्य है। जब जनता का ध्यान भटकाने के लिए कोई बात नहीं रह जाती है, तो अचानक नरेन्द्र मोदी को चुनावी खर्च बचाने के लिए एक देश एक चुनाव की बात याद आती है। मगर फिर वही ढाक के तीन पात! बहरहाल, चुनावों की घोषणा करने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से प्रेस कांफ्रेंस में जिस तरह के सवाल हुए, उनमें बार-बार यही नजर आया कि चुनाव आयोग की साख दरक चुकी है और उस पर भरोसा भी कम हुआ है। वहां मौजूद कई पत्रकारों ने एसआईआर, चुनावी हिंसा, भाजपा के दबाव आदि को लेकर सवाल किए। विपक्ष भी अक्सर यही सवाल उठाता है, लेकिन उसे जवाब की जगह उलाहना मिलती है। पत्रकारों के सवालों के जवाब तो ज्ञानेश कुमार ने दिए, मगर क्या वे कभी आत्ममंथन करेंगे कि उनसे ऐसे सवाल करने की नौबत क्यों आई। बहरहाल, प्रेस वार्ता में एक सवाल बंगाल चुनाव के सीमित चरणों पर हुआ। पिछली बार बंगाल में सुरक्षा का हवाला देकर आठ चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार केवल दो चरणों में हो रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ने इस बारे में कहा कि, 'पश्चिम बंगाल में चुनाव पहले के आठ चरणों के बजाय दो चरणों में आयोजित किए जाने के संबंध में, आयोग ने विस्तृत विचार-विमर्श किया और अपने विवेक से यह पाया कि चरणों की संख्या कम करना और इसे उस स्तर तक लाना आवश्यक है जहां यह सभी के लिए सुविधाजनक हो...' अब ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि क्या प.बंगाल में दो चरणों में चुनाव का फैसला कारगर होता है या नहीं। वैसे चुनाव आयोग ने रविवार आधी रात को प.बंगाल में मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना को उनके पदों से हटा दिया है। आयोग के आदेशानुसार नंदिनी चक्रवर्ती को चुनाव से जुड़े किसी भी काम से दूर रखा जाएगा। उनकी जगह 1993 बैच के आईएएस अधिकारी दुष्यंत नरियाल को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। गृह विभाग में प्रधान सचिव के पद पर 1997 बैच की आईएएस अधिकारी संघमित्रा घोष को लगाया गया है। इसके अलावा राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी पीयूष पांडे को हटाकर सिद्धनाथ गुप्ता को उनकी जगह लगाया गया है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर सुप्रतीम सरकार की जगह अजय कुमार नंद को कमिश्नर बनाया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह बदलाव राज्य में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण और बिना हिंसा के होंगे। इसी मक़सद से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि ये आदेश तुरंत लागू होंगे और सोमवार दोपहर 3 बजे तक नए अधिकारियों के पदभार ग्रहण की रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि शीर्ष अधिकारियों के तबादले के आदेश से हंगामा मच गया है। यह तबादला पश्चिम बंगाल में हाल के समय में बहुत बड़ा और असामान्य है। ममता बनर्जी ने इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरने की घोषणा की है। वहीं सोमवार को टीएमसी सांसदों ने संसद में हंगामा किया और राज्यसभा से पूरे दिन के लिए बहिर्गमन किया। लेकिन चुनाव आयोग के बचाव में एक बार फिर भाजपा सामने आ गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने टीएमसी के विरोध पर कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। सदन में उसकी आलोचना करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, 'अगर हर सदस्य अदालत या चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं के फैसलों पर सवाल उठाएगा तो यह ठीक नहीं। चुनाव आयोग को अलग शक्ति दी गई है।' उन्होंने टीएमसी और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं और सदन का समय बर्बाद करते हैं।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा है

“ टीटीपी का गठन 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के बाद की स्थिति से जुड़ा हुआ है। उस समय कई पाकिस्तानी उग्रवादी, जो अफगान लड़ाकों के साथ लड़ चुके थे, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हो गए क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के आतंकवाद विरोधी अभियान का समर्थन किया था।

सोमवार की देर रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हवाई हमला कर दिया। अफगानिस्तान के उप सरकारी प्रवक्ता ने इस हमले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में नशाखोरों का इलाज करने वाले एक अस्पताल को निशाना बनाया। इस हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 400 हो गई है। पाकिस्तान ने सोमवार की देर रात अफगानि-स्तान की राजधानी काबुल पर जो हवाई हमला कर दिया उसके बारे में अफगानिस्तान के उप सरकारी प्रवक्ता ने इस हमले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में नशाखोरों का इलाज करने वाले एक अस्पताल को निशाना बनाया। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में, हमदुल्लाह फितरत ने कहा कि सोमवार रात हुए हमले में अस्पताल का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। उन्होंने बताया कि अब तक मरने वालों की संख्या 400 हो गई है, जबकि 250 लोग घायल हुए हैं। फितरत ने कहा कि बचाव दल इमारत में लगी आग पर काबू पाने और पीड़ितों के शवों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं।अफ़गानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के विशेष दूत रिचर्ड बेनेट ने अस्पताल पर हुए हमले में आम नागरिकों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन ने भी हमले की निंदा करते हुए कहा है कि अस्पतालों जैसे सार्वजनिक स्थानों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। काबुल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि निवासियों ने शहर के ऊपर लगातार हवाई गतिविधियों की सूचना दी है। पाकिस्तानी सेना ने हाल के हफ्तों में कई बार काबुल पर हमले किए हैं, जिससे भारी संख्या में आम नागरिक हताहत हुए हैं। बता दें कि पाकिस्तान ने पहले अस्पताल को निशाना बनाने से इनकार किया था और कहा था कि सोमवार को काबुल और पूर्वी अफगानिस्तान में किए गए अन्य हमलों में किसी भी नागरिक स्थल को निशाना नहीं बनाया गया था। इसके अलावा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सेना पर हवाई हमलों में काबुल के उस अस्पताल को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जहां नशाखोरों का इलाज किया जाता है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि 400 से अधिक लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि पूर्वी अफगानिस्तान में किए गए हमलों में किसी भी नागरिक स्थल को निशाना नहीं बनाया गया था। अफगानिस्तानी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शराफत जमान ने बताया कि अस्पताल का पूरा हिस्सा नष्ट हो गया है। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने भी वीडियो पोस्ट किया। स्थानीय टेलीविजन स्टेशनों ने एक इमारत के मलबे में दमकलकर्मियों को आग बुझाने के लिए संघर्ष करते हुए फुटेज प्रसारित किया। यह कथित हमला अफगान अधिकारियों द्वारा दोनों पक्षों के बीच उनकी साझा सीमा पर गोलीबारी की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुआ, जिसमें अफगानिस्तान में चार लोग मारे गए। पड़ोसी देशों के बीच वर्षों में सबसे भीषण संघर्ष तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मोशर्रफ जैदी ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि काबुल में किसी भी अस्पताल को निशाना नहीं बनाया गया था। X पर एक पोस्ट में, पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने कहा कि हमलों में ₹काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान और अफगानि-स्तान स्थित पाकिस्तानी आतंकवादियों के सैन्य प्रतिष्ठानों और आतंकवादी समर्थन बुनियादी ढांचे, जिनमें तकनीकी उपकरण और गोला-बारूद भंडार शामिल हैं, को सटीक रूप से निशाना बनाया गया था। मंत्रालय ने कहा कि इन सुविधाओं का इस्तेमाल निर्दोष पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ किया जा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान का लक्ष्यीकरण सटीक और सावधानीपूर्वक किया गया था ताकि कोई भी अप्रत्यक्ष नुकसान न हो। यही नहीं बताया जा रहा है कि हमले के बाद यहां स्थित एक बड़े कमर्शियल मार्केट में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते करीब 150 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गईं और व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला रिहायशी और व्यावसायिक इलाके के करीब हुआ, जिससे लोगों में डर और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर इस घटना के खौफनाक वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें जलकर राख हुआ बाजार साफ दिखाई दे रहा है। स्थानीय बख्तावर न्यूज एजेंसी के हवाले से मेयर मौलवी अब्दुल्ला मुस्तफा बताया कि रविवार सुबह करीब 4 बजे शहर की ओर कई गोले दागे गए। ये गोले एक बाजार में गिर गए, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ी।ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर दोनों देश आपस में क्यों लड़ रहे हैं। खुद को मुसलमानों का लीडर बताने वाला मुल्क पाकिस्तान आखिर मासूमों की जान क्यों ले रहा है? आइये जानते हैं पूरी डिटेल इस संघर्ष के पीछे मुख्य कारण पाकिस्तान का यह आरोप है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को सुरक्षित ठिकाने दे रहा है। टीटीपी को पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। पाकिस्तान का कहना है कि यह संगठन अफगानिस्तान की जमीन से काम कर रहा है, जबकि अफगान तालिबान बार-बार इस आरोप से इनकार करता रहा है।अक्टू-बर 2025 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक हवाई हमला भी किया था। पाकिस्तान की सेना ने कहा था कि यह हमला पाकिस्तान में आतंकवाद से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच सबसे घातक टकराव हुआ, जो 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से सबसे बड़ा माना गया।

■ अशोक भाटिया

जन सुराज का...

रामस्वरूप रावतसरे

'महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026' - अवैध धर्मांतरण व 'लव जिहाद' पर लगाम

'महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2026' महाराष्ट्र विधानसभा में पेश हो चुका है। इसमें लालच, बहला-फुसला कर या झाँसा देकर अवैध तरीके से कराए गए धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्ती बरती गई है। ऐसे मामले में 7 साल जेल और 1 लाख से 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। धर्मांतरण से 60 दिन पहले सूचित करने को भी अनिवार्य कर दिया गया है। नाबालिग, महिला, एससी-एसटी और मानसिक रूप से अस्वस्थ्य व्यक्ति के केस में सजा का प्रावधान ज्यादा है। बार-बार ऐसा करने पर आरोपितों को 10 साल सजा दी जा सकती है। धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 के अनुसार अगर किसी महिला की जबरदस्ती या झाँसे में लेकर शादी कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में जो बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को माँ के मूल धर्म का माना जाएगा, यानी वह धर्म जो धर्मांतरण से पहले वह अपनाती थी। इस केस में बच्चे को माता-पिता की संपत्ति से भरण-पोषण पाने का अधिकार भी मिलेगा। कानून में 'ब्रेनवॉशिंग' को अपराध माना गया है। बिल में 'शिक्षा के माध्यम से ब्रेनवॉशिंग' को अवैध धर्मांतरण का जरिया बताया गया है। इसमें एक धर्म को दूसरे से बेहतर बताना भी 'लालच' की श्रेणी में आएगा। साथ ही, किसी धर्म के रीति-रिवाजों को नकारात्मक तरीके से पेश करना 'अवैध प्रभाव' की श्रेणी में आएगा। जानकारी के अनुसार विधेयक में पुलिस को कार्रवाई की विशेष शक्ति दी गई है। पुलिस को अगर लगता है कि जबरन धर्मांतरण हुआ है या कानून का पालन नहीं किया गया है तो बिना औपचारिक शिकायत के भी स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने कर सकती है। इस विधेयक में 'प्रलोभन' का दायरा बढ़ा दिया गया है। शिक्षा के अलावा, पैसा देकर या गिफ्ट देकर, रोजगार की सुविधा मुहैया कराकर या फिर धार्मिक संस्थानों द्वारा मुफ्त शिक्षा देकर धर्मांतरण करना 'लालच' की श्रेणी में ही आएगा। विधेयक में संस्थाओं पर कार्रवाई का भी प्रावधान है। यदि कोई संस्था या संगठन इसमें शामिल

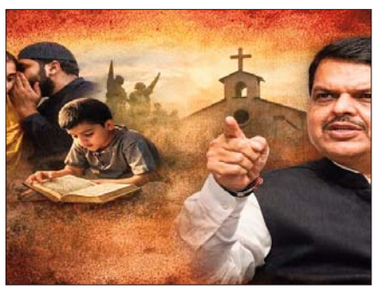

पाया जाता है तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है और जिम्मेदार लोगों को 7 साल तक की जेल हो सकती है। विधेयक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना देनी होगी। इसमें व्यक्ति का नाम, उम्र, किस धर्म में है, किसे ज्वाइंन करना है- जैसी जानकारी देनी होगी। इसके बाद स्थानीय जिला प्रशासन इसकी जाँच करेगा कि वह व्यक्ति किसी दबाव में या लालच में धर्मांतरण तो नहीं कर रहा। सारी जाँच के बाद ही उसे धर्मांतरण की अनुमति दी जाएगी। शादी के 25 दिन के अंदर इसका पंजीकरण करना भी जरूरी होगा, वरना इसे मान्यता नहीं दी जाएगी। अगर कोई कानून का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धर्म परिवर्तन के नियमों का पालन अगर नहीं किया जाता है, तो धर्मांतरण को अवैध घोषित किया जाएगा। उसे जेल और जुर्माना या दोनों सजा का सामना करना पड़ सकता है। उसे 7 साल जेल हो सकती है। एक लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर मामला किसी महिला, नाबालिग,एससी, एसटी से जुड़ा होता है तो 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पिछले 8 सालों में भाजपा शासित कई सरकारों ने इस तरह के धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाए हैं, ताकि किसी व्यक्ति को, खासकर महिलाओं को आसानी से अवैध तरीके से धर्मांतरण नहीं कराया जा सके। इन कानूनों का मकसद लव जिहाद से हिंदू लड़कियों और महिलाओं को छुटकारा दिलाना है। उन्हें जबरदस्ती धर्म-परिवर्तन कराने और शादी कराने से रोकना है। 2017 से 9 राज्यों ने अवैध धर्म-परिवर्तन को रोकने कानून बनाए गए। इनमें 2017 में झारखंड, 2018 में उत्तराखंड , 2019 में हिमाचल प्रदेश, 2020 में उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में 2021 में कानून बनाया गया। हरियाणा और कर्नाटक में 2022 जबकि राजस्थान में 2025 में कानून बना। इन सभी कानूनों का घोषित मकसद जोर-जबरदस्ती, धोखाधड़ी और लालच देकर योजनाबद्ध तरीके से धर्म-परिवर्तन कराने पर लगाम लगाना है। इन सभी जगहों पर धर्मांतरण से पहले स्थानीय प्रशासन से इजाजत लेना जरूरी है। गैर-कानूनी धर्म-परिवर्तन के मामले में आपराधिक मुकदमों में सबूत देने की जिम्मेदारी आरोपित पर होती है। जानकारों के अनुसार ये कानून देश में हो रहे सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद से लोगों को बचाने के लिए जरूरी है। लड़कियों को प्रेमजाल में फँसा कर आए दिन धर्म परिवर्तन कराने की घटनाएँ सामने आ रही हैं। ऐसे मामले जिसमें लड़कियाँ अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करती हैं और शादी करती है, उन्हें 60 दिन पहले बताने में क्या दिक्कत है। उन्हें 25 दिन के अंदर पंजीकरण कराने से भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिक्कत तो नाम बदल कर लड़की को प्रेमजाल में फँसा कर अवैध संबंध बनाने में है क्योंकि इसका मकसद सिर्फ लड़की को प्यार से या दबाव डालकर धर्मांतरण के लिए मजबूर करना है। उससे निकाह कर प्रताड़ित करना है। ऐसे मामलों में धर्मांतरण और निकाह एक हथियार की तरह इस्तेमाल होते हैं ताकि लड़की को काबू में रखा जा सके। उसका शोषण किया जा सके। अपने परिजनों की इच्छा के विरुद्ध गई लड़की को सामाजिक मदद भी मिलना मुश्किल हो जाता है।

अब सरकार ने...

ज्ञान चंद पाटनी

सोनम वांगचुक की हिरासत और रिहाई से एनएसए पर फिर उठे सवाल

सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक की करीब छह माह लंबी जेल यात्रा का अंत हो गया है। वांगचुक की हिरासत से लेकर रिहाई तक के घटनाक्रम से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत बन्दी बनाए गए थे। अब सरकार ने वांगचुक पर एनएसए हटा दिया और कहा कि यह निर्णय 'रचनात्मक और सार्थक संवाद' को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। अचानक जोधपुर जेल से सोनम वांगचुक की रिहाई के बावजूद यह साफ है कि देश में शांतिपूर्ण आंदोलनों को दबाने के लिए भी सबसे कठोर कानूनों का सहारा लिया जाता है। उच्चतम न्यायालय में वांगचुक की पत्नी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके हिरासत को चुनौती थी। इसकी सुनवाई के दौरान केंद्र ने आरोप लगाया था कि सोनम वांगचुक ₹ सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 'अरब स्प्रिंग' जैसा विद्रोह चाहते थे। यह भी आरोप लगाया गया कि वांगचुक ने युवाओं को नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हिंसक जेन-जेड विरोध प्रदर्शनों के लिए उकसाया। यहां तक कहा गया कि गांधीवादी अहिंसा का जिक्र केवल एक दिखावा था। इसके अलावा, वांगचुक पर कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग करने जैसे आरोप भी लगाए गए। लद्दाखी लोगों को युद्ध के समय भारतीय सेना की मदद न करने के लिए उकसाने के आरोप भी लगाए गए। इन सभी आरोपों को सोनम वांगचुक ने गलत बताया था। अब सरकार ने वांगचुक की हिरासत रद्द करके एक तरह से अपने ही आरोपों को गलत साबित कर दिया है। दरअसल, सोनम वांगचुक के अनशन के दौरान 24 सितंबर 2025 को लेह हिंसा हुई थी। दो दिन बाद 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत वांगचुक को हिरासत में लिया था। इसके बाद उन्हें फौरन जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया

गया था। वे करीब छह माह से जोधपुर जेल में ही थे। अब उनकी रिहाई हो गई है। एनएसए सरकार को ऐसे लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है, जिनसे देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो। इसके तहत किसी व्यक्ति को 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। 24 सितंबर को हुई मौतों का ठीकरा उनके सिर फोड़ा गया। लेकिन छह माह बाद सरकार का निष्कर्ष बदला और कहा गया— 'लद्दाख की समस्याओं का हल संवाद और बातचीत से ही संभव है'। सोनम वांगचुक पर्यावरण संरक्षण के लिए बरसों से काम कर रहे हैं। हिमालयी पारिस्थितिकी को बचाने के लिए उन्होंने एक तरह से अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने और छठी अनुसूची की मांग तेज हुई है। उनका मानना है कि बिना संवैधानिक सुरक्षा के लद्दाखी संस्कृति, भूमि और पर्यावरण खतरे में है। चीनी घुसपैठ, खनन माफियाओं और पर्यावरणीय क्षति के खिलाफ उनका आंदोलन शांतिपूर्ण था। अपनी मांगों के समर्थन में अनशन, पदयात्रा, जन जागरण जैसे कदम उठाए, लेकिन 24 सितंबर को लेह में प्रदर्शन के दौरान हुई मौतों ने माहौल गरमा दिया। इसके बाद वांगचुक को गिरफ्तार कर एनएसए लगा दिया गया, वे बिना मुकदमे के छह माह तक जेल में रहे।

जरा हटके

इसी प्रकार पड़ोसी ...

गजेंद्र सिंह

सोनिया गांधी के लेख : नैतिकता, कूटनीति और राजनीति

हाल के समय में सोनिया गांधी द्वारा लिखे गए लेख और वक्तव्य सार्वजनिक बहस का विषय बने हुए हैं। एक ओर मार्च 2026 में प्रकाशित उनके लेख में उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता और शिया धर्मगुरु अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या पर भारत सरकार की चुप्पी को लेकर प्रश्न उठाए। वहीं जून 2025 में लिखे गए अपने एक अन्य लेख में उन्होंने गाज़ा में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में भारत की प्रतिक्रिया को लेकर आलोचना की थी। इन दोनों लेखों में उनका तर्क यह रहा कि भारत की विदेश नीति को नैतिकता, अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवीय मूल्यों के आधार पर स्पष्ट आवाज उठानी चाहिए परंतु इन वक्तव्यों के साथ एक व्यापक प्रश्न भी सामने आता है— क्या यह वास्तव में सिद्धांत आधारित कूटनीति का आग्रह है या फिर ऐसी चयनात्मक नैतिकता जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं और भारत के राष्ट्रीय हितों को पर्याप्त महत्व नहीं देती? सबसे पहले उस विचार की चर्चा आवश्यक है जिसे अक्सर “नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ” कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने वाले अनेक विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी व्यवस्था वर्षों से कमजोर पड़ चुकी है। विश्व राजनीति आज आदर्शों से अधिक शक्ति संतुलन, रणनीतिक हितों और गठबंधनों पर आधारित है। पश्चिम एशिया के संघर्षों से लेकर पूर्वी यूरोप और इंडो-पैसिफिक तक, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता की भाषा अक्सर वास्तविक शक्ति राजनीति से पीछे रह जाती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई नेता वैश्विक घटनाओं को केवल नैतिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है और भू-राजनीतिक वास्तविकताओं की अनदेखी करता है तो उसका दृष्टिकोण अधूरा प्रतीत हो सकता है। इस आलोचना का दूसरा पहलू चयनात्मक नैतिक आक्रोश है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर नैतिक भाषा तो प्रबल रूप से सामने आती है लेकिन भारत के अपने ऐतिहासिक अनुभवों पर वही तीव्रता दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए, 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन और उनके विरुद्ध हिंसा आधुनिक भारत के सबसे पीड़ादायक अध्यायों में से एक है। हजारों परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े और वे दशकों से विस्थापन का जीवन जी रहे हैं। इसी प्रकार पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा और भेदभाव की घटनाएँ समय-समय पर चर्चा में आती रही हैं। आलोचकों के अनुसार, यदि अंतरराष्ट्रीय नैतिकता की बात की जाती है तो इन विषयों पर भी समान संवेदनशीलता अपेक्षित है। वाद का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष ईरान की राजनीतिक संरचना से जुड़ा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को अक्सर “राष्ट्र प्रमुख” के रूप में संबोधित किया जाता है लेकिन उनकी नियुक्ति प्रक्रिया सामान्य लोकतांत्रिक चुनाव से भिन्न है। ईरान में सर्वोच्च नेता का चयन विशेषज्ञों की सभा नामक इस्लामिक निकाय द्वारा किया जाता है जो मुख्यतः धर्मगुरुओं का समूह है। आलोचकों के अनुसार यह व्यवस्था लोकतांत्रिक जनादेश की बजाय एक इस्लामिक -राजनीतिक ढाँचे पर आधारित है। ईरान की सरकार पर सबसे गंभीर आरोप महिलाओं के अधिकारों और राजनीतिक असहमति के दमन से जुड़े हैं। 2022 में महसा अमीनी की मृत्यु के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों ने दुनिया का ध्यान इस विषय की ओर खींचा। इन आंदोलनों के दौरान सुरक्षा बलों, विशेष रूप से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर पर प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के आरोप लगाए गए। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इसे राजनीतिक असहमति के दमन का उदाहरण बताया। पश्चिम एशिया की राजनीति में ईरान की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू उसके क्षेत्रीय प्रभाव से जुड़ा हुआ है। यह प्रभाव उन संगठनों के माध्यम से भी देखा जाता है जिन्हें विभिन्न स्तरों पर तेहरान का समर्थन मिलने की बात अंतरराष्ट्रीय विश्लेषणों में कही जाती रही है। इनमें प्रमुख रूप से हमास, हिज़्बुल्लाह और हूती जैसे समूह शामिल हैं। पश्चिम एशिया के अलग-अलग संघर्षों और राजनीतिक समीकरणों में इन संगठनों की सक्रिय भूमिका रही है और ईरान के साथ उनके संबंध लंबे समय से वैश्विक कूटनीतिक बहस, क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं और अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण का विषय बने हुए हैं। अंततः यह बहस एक बड़े प्रश्न की ओर ले जाती है— भारत की विदेश नीति का आधार क्या होना चाहिए? अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अक्सर नैतिक मूल्यों और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। अधिकांश देश अपने कूटनीतिक निर्णयों में मानवाधिकार, रणनीतिक हित, सुरक्षा और आर्थिक संबंधों जैसे कई कारकों को साथ लेकर चलते हैं। आलोचकों का तर्क है कि यदि नैतिकता की भाषा का उपयोग किया जाए तो उसे सुसंगत और संतुलित होना चाहिए— ऐसा न लगे कि वह केवल राजनीतिक सुविधा के अनुसार सामने आती है। विदेश नीति के प्रश्न केवल आदर्श और नैतिकता के आधार पर नहीं सुलझते; वे इतिहास, रणनीति, शक्ति संतुलन और राष्ट्रीय हितों से भी प्रभावित होते हैं। इसलिए जब किसी नेता द्वारा वैश्विक नैतिकता की बात की जाती है, तो उससे अपेक्षा होती है कि वह दृष्टिकोण सार्वभौमिक और संतुलित हो— ऐसा दृष्टिकोण जो दूरस्थ संघर्षों के साथ-साथ उन मुद्दों को भी समान गंभीरता से देखे जिन्होंने भारत के अपने समाज और इतिहास को गहराई से प्रभावित किया है।

कमिंस बैक इंजरी के कारण शुरुआती मैचों से बाहर, झारखंड को पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दिलाई

ईशान किशन कर सकते हैं एसआरएच की कप्तानी

नई दिल्ली, एजेंसी

सनराइजर्स हैदराबाद के नियमित कप्तान पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन IPL 2026 की शुरुआत में टीम की कप्तानी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमिंस अभी बैक इंजरी से उबर रहे हैं और यह साफ नहीं है कि वे कब टीम से जुड़ेंगे। कमिंस को यह चोट 2025-26 एशेज सीरीज से पहले लगी थी। शुरुआत में माना जा रहा था कि वे पूरी सीरीज मिस करेंगे,लेकिन उन्होंने एक टेस्ट खेला और फिर दोबारा टीम से बाहर हो गए। हालांकि, ईशान को शुरुआती मैचों की कप्तानी सौंपे जाने को लेकर फ्रेंचाइजी की ओर से अभी कुछ नहीं कहा गया है। टी-20 वर्ल्ड कप में ईशान ने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाया है कि वे वहां काफी सहज हैं। ईशान किशन ने अपनी कप्तानी में झारखंड को पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब दिलाया है। कप्तानी के साथ-साथ ईशान बल्ले से भी बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने उस टूर्नामेंट में 197.33 की स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 517 रन बनाए थे। इसी अनुभव के दम पर वे कप्तानी की रेस में अभिषेक शर्मा से आगे हैं।

पैट कमिंस के बिना हैदराबाद की बॉलिंग यूनिट थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईशान के लिए सबसे बड़ी चुनौती गेंदबाजों का सही इस्तेमाल करना होगी। हालांकि टीम के पास कुछ अच्छे विकल्प हैं, लेकिन कमिंस जैसा लीडर मैदान पर न होना टीम के लिए एक कमी साबित हो सकता है।

ईशान किशन के पक्ष में गया कप्तानी का अनुभव

ईशान किशन ने अपनी कप्तानी में झारखंड को पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब दिलाया है। कप्तानी के साथ-साथ ईशान बल्ले से भी बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने उस टूर्नामेंट में 197.33 की स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 517 रन बनाए थे। इसी अनुभव के दम पर वे कप्तानी की रेस में अभिषेक शर्मा से आगे हैं। हालांकि,पिछले IPL सीजन में ईशान का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा था। उन्होंने टीम के लिए पहले मैच में शतक लगाया था और सीजन के आखिर में नाबाद 94 रन की पारी भी खेली थी,लेकिन बीच में वे लगातार रन नहीं बना पाए थे।

वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड सीरीज में मचाया धमाल

पिछले IPL सीजन में ईशान थोड़े इनकंसिस्टेंट थे, लेकिन पिछले एक महीने में उन्होंने अपनी फॉर्म से सभी आलोचकों को जवाब दिया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार खेल के बाद उनकी टीम इंडिया के टी-20 स्क्वॉड में वापसी हुई। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज और 2026 टी-20 वर्ल्ड कप में कुल 532 रन बनाए। जहां उनका स्ट्राइक रेट 207 का रहा।

नहीं बदलेगी अभिषेक-ट्रैविस हेड की ओपनिंग जोड़ी

ईशान किशन की कप्तानी मिलने के बाद टीम के बैटिंग ऑर्डर को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में SRH को अपनी हिट ओपनिंग जोड़ी अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईशान तीसरे नंबर पर आकर मिडिल ऑर्डर को मजबूती दे सकते हैं।

अफगान क्रिकेटर्स काबुल एयरस्ट्राइक पर भड़के

नवीन ने कहा- पाकिस्तान और इजराइल में कोई फर्क नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी

पाकिस्तान ने सोमवार रात एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया, जिनमें एक हॉस्पिटल भी शामिल है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें 400 लोगों की मौत हो गई, वहीं 250 से ज्यादा घायल हैं। इस घटना के बाद अफगानिस्तान के कई क्रिकेटर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राशिद खान, नवीन उल हक और मोहम्मद नबी ने दुख जताया है। अफगानिस्तान के स्टार ऑलराउंडर राशिद खान ने भी काबुल में हुए एयरस्ट्राइक पर गहरा दुख जताया है। राशिद ने एक्स पर लिखा, काबुल में पाकिस्तानी हवाई हमलों के कारण आम लोगों के मारे जाने की

खबरों से मुझे गहरा दुख हुआ है। आम नागरिकों के घरों, शिक्षण संस्थानों या मेडिकल सुविधाओं को निशाना बनाना, चाहे जान-बूझकर हो या गलती से, एक युद्ध अपराध है। राशिद ने आगे लिखा, इंसानी जानों की जिस तरह से अनदेखी की जा रही है, खासकर रमजान के पवित्र महीने में, वह बेहद घिनौनी और गहरी चिंता का विषय है। इससे केवल फूट और नफरत ही बढ़ेगी। मैं संयुक्त राष्ट्र (UN) और मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली अन्य एजेंसियों से अपील करता हूं कि वे इस इस जुल्म की पूरी तरह से जांच करें और इसके दोषियों को सजा दिलवाएं। इस मुश्किल समय में मैं अपने अफगान लोगों के साथ खड़ा हूं। हम इस सदमे से उबरेंगे, और एक राष्ट्र के तौर पर हम फिर से उठ खड़े होंगे। हम हमेशा ऐसा ही करते आए हैं। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने ट्वीट किया, आज रात, हमने यहां काबुल में एक जोरदार धमाका सुना। इसके तुरंत बाद पाकिस्तानी हवाई हमलों की चपेट में आए एक अस्पताल से आग की लपटें आसमान में उठने लगीं। रमजान के महीने में जब लोगों ने अपना रोजा खोला ही था, तब बेगुनाह जानें चली गईं और कई अन्य घायल हो गए।

फास्ट न्यूज

ईंधन बचाने के लिए कड़े नियम लागू

नई दिल्ली। श्रीलंका की सरकार ने देश में काम के दिनों को घटाकर हफ्ते में केवल चार दिन करने का फैसला लिया है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के लंबे समय तक चलने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। सरकार का मुख्य मकसद देश में मौजूद ईंधन (फ्यूल) के सीमित भंडार को बचाना है। दरअसल, अमेरिका और इस्राइल के साथ चल रहे युद्ध के जवाब में ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू-मध्य को बंद कर दिया है।

सेंसेक्स 568 अंक चढ़कर 76071 पर बंद

मुंबई। शेयर बाजार में आज यानी 17 मार्च को बढ़त रही। सेंसेक्स 568 अंक की तेजी के साथ 76,071 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 172 अंक की बढ़त रही, ये 23,581 पर बंद हुआ। आज एनर्जी, बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में बढ़त रही। एग्रोकेमिकल कंपनी GSP क्रॉप साइंस का IPO 16 मार्च से ओपन हो चुका है। इसमें आम निवेशक 18 मार्च तक पैसा लगा सकेंगे। कंपनी इस मेनलाइन इश्यू के जरिए 400 करोड़ जुटाना चाहती है। इसमें मिनिमम 14,720 रुपए लगाने होंगे। इससे पहले कल यानी 16 मार्च को शेयर बाजार में तेजी रही थी। सेंसेक्स 938 अंक की तेजी के साथ 75,502 के स्तर पर बंद हुआ था। निफ्टी में भी 257 अंक की तेजी रही, ये 23,408 के स्तर पर बंद हुआ था। डाउ जोन्स 387 अंक (0.83%) बढ़कर 46,946 के स्तर पर बंद हुआ। टेक बेस्ड इंडेक्स नैस्डैक कंपोजिट 1.22% गिरकर 22,374 पर बंद हुआ।

मार्च में साइन होने वाली भारत-अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील टली

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली अंतरिम ट्रेड डील अब कुछ समय के लिए टल गई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह डील अब तभी साइन होगी, जब अमेरिका अपना नया ग्लोबल टैरिफ स्ट्रक्चर तैयार कर लेगा। दरअसल, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में डोनाल्ड ट्रम्प की उन शक्तियों को खत्म कर दिया है।

सलमान के पिता सलीम खान अस्पताल से डिस्चार्ज

1 महीने से लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट, ब्रेन हैमरेज के बाद हुई थी सर्जरी

मुंबई, एजेंसी

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पिता और स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान को आज मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 90 साल के सलीम खान को ब्रेन हेमरेज के कारण 17 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब एक महीने तक चले इलाज के बाद अब उनकी तबीयत में काफी सुधार है और डॉक्टर्स ने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक उनका डिस्चार्ज प्रोसीजर पूरा हो चुका है, लेकिन वे अभी हॉस्पिटल में ही हैं। सलीम खान सीनियर कंसल्टेंट डॉ. जलील पारकर की देखरेख में थे। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक, बढ़ती उम्र की वजह से उन्हें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे। जांच में

मामूली ब्रेन हैमरेज की बात सामने आई थी, जिसके बाद न्यूरोसर्जन डॉ. नितिन डांगे ने उनकी एक छोटी सर्जरी (DSA प्रोसीजर) की थी। उनकी उम्र को देखते हुए रिकवरी में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब वे पूरी तरह स्टेबल हैं। इलाज के शुरुआती दौर में सलीम खान को कुछ समय के लिए वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। डॉ. जलील पारकर ने बताया था कि हैमरेज के बाद छोटा प्रोसीजर जरूरी था जो सफल रहा। हाल ही में एक इफ्तार पार्टी के दौरान अरबाज खान ने पैपराजजी से बात करते हुए बताया था कि पिता की सेहत अब काफी बेहतर है और वे सुधार कर रहे हैं। सलीम खान के अस्पताल में रहने के दौरान पूरा खान परिवार उनके साथ खड़ा रहा। बेटे सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान लगातार अस्पताल के पहुंचते रहे। शाहरुख खान और आमिर खान भी सलीम खान का हाल जानने अस्पताल पहुंचे थे। इसके अलावा, सलीम खान के पुराने साथी और दिग्गज लेखक जावेद अख्तर ने भी अस्पताल जाकर अपने दोस्त की सेहत की जानकारी ली थी। सलीम खान ने 60 के दशक में बतौर अभिनेता अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 'तीसरी मंजिल' जैसी फिल्मों में छोटे रोल किए, लेकिन बाद में उन्होंने राइटिंग को अपना पेशा बनाया।

एडवोकेट की चंडीगढ़ एसएसपी को शिकायत, कहा- सॉन्ग में डबल मीनिंग बोल, बैन किया जाए

संजय दत्त-नोरा का गाना सरके चुनर तेरी विवादों में

चंडीगढ़, एजेंसी

अप्रैल में रिलीज होने वाली फिल्म केडीः द डेविल के गाने 'सरके चुनर तेरी सरके को लेकर विवाद हो गया है। चंडीगढ़ काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन एवं पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने मंगलवार को चंडीगढ़ के एसएसपी को शिकायत दी है। उन्होंने कहा कि गाने में डबल मीनिंग बोल हैं। इसके साथ आपत्तिजनक सीन दिखाए गए हैं। यह न सिर्फ समाज की शालीनता के खिलाफ है, बल्कि खासकर बच्चों और कम उम्र के युवाओं के मन पर बुरा असर डाल सकता है। यह सार्वजनिक शालीनता के लिए अपमानजनक है इस गाने में नोरा फतेही और संजय दत्त नजर

आए हैं, जबकि इसके गीतकार रकीब आलम हैं। पुलिस से उन्होंने मांग की है कि वायरल हो रहे अश्लील गाने के मामले में तुरंत BNS की धारा 294, 296, 79 तथा आईटी एक्ट की धारा 67 व 67A के तहत FIR दर्ज की जाए और गाना सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अश्लीलता को बढ़ावा देना कानूनन अपराध है। यह गाना दो दिन पहले 15 मार्च को रिलीज हुआ।

इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड ने ये गाना कैसे रिलीज होने दिया। शिकायत की कॉपी गृहमंत्री अमित शाह को भी भेजी गई है। उन्होंने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जरूरत पड़ी तो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा।

लोगों का भी फूटा गुस्सा

गाने को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, कई यूजर्स इसे 'वलगर' और 'भद्दा' बता रहे हैं। सिंगर अरमान मलिक ने भी एक्स पर पोस्ट कर गाने के लिरिक्स पर नाराजगी जताई है।

सिख और पाकिस्तानियों में विवाद

पंजाबी रेस्टोरेंट मालिक ने हलाल मीट न बेचने का बोर्ड लगाया, 100 लोगों ने हमला किया

जालंधर, एजेंसी

लंदन के हाई-प्रोफाइल इलाके हैमरस्मिथ में पंजाबी रेस्टोरेंट मालिक और पाकिस्तानी मुस्लिमों में हलाल मीट को लेकर विवाद हो गया। 16 साल से रेस्टोरेंट चला रहे हरमन कपूर ने कहा कि हलाल मीट बेचने से मना करने पर पाकिस्तानियों के 100 लोगों के ग्रुप ने हमला कर दिया। उन्होंने कहा- मुझे हलाल मीट बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अपने बिजनेस को बचाने के लिए मुझे दुनियाभर के सिखों से मदद मांगनी पड़ रही है। हरमन के मुताबिक, विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने 14 मार्च को रेस्टोरेंट पर एक बोर्ड लगा दिया। इस पर साफ लिख दिया कि उनके रंगरेज रेस्टोरेंट में हलाल मीट नहीं मिलेगा। हरमन के पोस्टर लगाने के बाद रेस्टोरेंट पर पाकिस्तानियों की भीड़ जमा हो गई। यहां तोड़फोड़ की कोशिश की गई। हरमन ने कहा कि उन पर हमला किया गया। उन्होंने गातरे से डिफेंस किया। उनके घर को

भी कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया। हरमन ने कहा कि पुलिस ने भी कट्टर-पंथियों का साथ दिया। आरोपियों को अरेस्ट करने के बजाय उल्टा उन्हें ही अरेस्ट कर लिया। लेकिन पूछताछ के बाद छोड़ दिया। हरमन ने बताया कि 2010 में खोला उनका रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है। उनका रेस्टोरेंट रंगरेज पंजाबी स्वाद के लिए मशहूर है। लेकिन उन्होंने कभी हलाल मीट नहीं बेचा। 14 मार्च 2026 को कपूर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- नॉन हलाल मीटअप। दोपहर 2 बजे रंगरेज आओ, रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर आओ। विवाद करने वालों को एक्सपोज करेंगे। पोस्ट वायरल होते ही मुस्लिम समुदाय के 100 से ज्यादा लोग रेस्टोरेंट के बाहर जमा हो गए। एंट्रेंस बंद होने पर नारे लगाने लगे। कपूर ने इसका वीडियो पोस्ट कर दिया और कहा कि उसे धमकियां आ रही हैं। रंगरेज रेस्टोरेंट के बाहर हंगामा होने के बाद पुलिस फोर्स पहुंची। भीड़ को हटाया। पुलिस अंदर घुसी और हरमन सिंह कपूर को अरेस्ट कर ले गई। पुलिस ने गिरफ्तारी का कारण हमला करने वालों को गातरा दिखाना बताया। पुलिस ने कहा कि लंदन में हथियार दिखाना कानूनी जुर्म है। कपूर को बाद में बेल मिल गई। इसे लेकर मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हैरानी की बात यह रही कि पुलिस ने भीड़ को हटाने के बजाय हरमन कपूर को ही गिरफ्तार कर लिया। उन पर कृपाण रखने और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तनाव बढ़ाने का आरोप लगा। इस कार्रवाई ने ब्रिटेन में दोहरी पुलिसिंग की बहस छेड़ दी है, जहां पीड़ित को ही आरोपी मानकर गिरफ्तार कर लिया गया और भीड़ सुरक्षित रही।

ईरान के साथ जंग में अकेले पड़े ट्रम्प

नाटो देश बोले- ये हमारी लड़ाई नहीं, होर्मुज का रास्ता खुलवाने से इनकार

वॉशिंगटन, एजेंसी

ईरान में खामेनेई समेत 40 से भी ज्यादा अधिकारियों के मारे जाने के बाद अमेरिका को यह जंग बड़ी कामयाबी नजर आ रही थी। लेकिन 17 दिन बाद हालात बदल चुके हैं। युद्ध का कोई साफ अंत नजर नहीं आ रहा है। ईरान ने जवाब में होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते तेल आपूर्ति रोक दी, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट पहुंची है। ट्रम्प अब अपने सहयोगी नाटो देशों से होर्मुज में रास्ता खुलवाने की अपील कर रहे हैं। हालांकि इन देशों ने साफ कर दिया है कि वे होर्मुज स्ट्रेट में अपने वॉरशिप नहीं भेजेंगे। यह फैसला ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चेतावनी दी थी कि अगर नाटो देश इस अहम समुद्री रास्ते को फिर से खोलने में मदद नहीं करते, तो नाटो का भविष्य खराब हो सकता है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने भी अमेरिका पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा कि यह यूरोप का युद्ध नहीं है और जब अमेरिकी नौसेना खुद इतनी ताकतवर है, तो कुछ यूरोपीय जहाज क्या कर लेंगे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने कहा कि इस संकट का हल बातचीत से ही निकलना चाहिए और उनका देश किसी नौसैनिक मिशन को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोपीय यूनियन के मौजूदा मिशन सिर्फ समुद्री डकैती रोकने और रक्षा के लिए हैं, उन्हें युद्ध में नहीं बदला जा सकता।

जर्मनी बोला- यह यूरोप की जंग नहीं

द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी ने साफ कहा है कि वह किसी भी सैन्य कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि इस मामले में कभी कोई फैसला नहीं हुआ, इसलिए जर्मनी के सैन्य योगदान का सवाल ही नहीं उठता।

ब्रिटेन बोला- हम इस युद्ध में नहीं फंसेंगे

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि उनका देश इस बड़े युद्ध में नहीं फंसेगा। उन्होंने माना कि होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना जरूरी है ताकि तेल बाजार स्थिर रहे, लेकिन यह आसान काम नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी कदम ज्यादा से ज्यादा देशों की सहमति से ही उठाया जाएगा। यूरोपीय देशों ने सैन्य कार्रवाई की बजाय कूटनीति पर जोर दिया है। होर्मुज स्ट्रेट बहुत अहम है क्योंकि यहां से दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है, जो फिलहाल ईरान के कारण प्रभावित हो रही है।

कैफे ने नींबू पानी पर 5% गैस-क्राइसिस चार्ज वसूला

यूजर्स बोले- इसे बनाने में कौन सी गैस लगती है

बेंगलुरु, एजेंसी

देशभर में जारी LPG संकट के बीच बेंगलुरु के एक कैफे ने अपने ग्राहक को नींबू पानी के बिल पर 5% 'गैस क्राइसिस चार्ज' (गैस संकट शुल्क) लगा दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कैफे की रसीद की फोटो वायरल होने के बाद लोग इस पर तरह-तरह की रिएक्शन दे रहे हैं। बेंगलुरु के 'थियो कैफे' की इस वायरल रसीद के मुताबिक, एक ग्राहक ने दो मिंट लेमोनेड (नींबू पानी) ऑर्डर किए थे। एक लेमोनेड की कीमत 179 थी, यानी दो के लिए 358 हुए। कैफे ने पहले 17.90 का 5% डिस्काउंट दिया, लेकिन फिर स्टैंडर्ड GST (CGST और SGST) के साथ 'गैस क्राइसिस चार्ज' के नाम पर 5% यानी 17.01 अलग से जोड़ दिए। इस तरह ग्राहक का कुल बिल 374 हो गया। X पर बिल की फोटो शेयर होते ही यूजर्स ने कैफे की

आलोचना की। लोगों ने सवाल पूछा कि नींबू पानी बनाने में आखिर कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, जो इसके लिए 'क्राइसिस शुल्क' वसूला जा रहा है? कुछ यूजर्स ने इसे ग्राहकों को लूटने का नया बहाना बताया, तो कुछ ने इसे 'महंगाई का डिजिटल अवतार' बताया। शिवालिक जहाज पर करीब 46 हजार मीट्रिक टन LPG लदी है, जो लगभग 32.4 लाख घरेलू गैस सिलेंडरों के बराबर बताई जा रही है।

सभी को ई-केवाईसी की जरूरत नहीं, केवल वे लोग कराएं जिनका रिकॉर्ड अधूरा

गैस कनेक्शन बंद होने की खबरों पर सरकार की सफाई

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्र सरकार ने उन खबरों पर जवाब दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि अगर ग्राहकों ने e-KYC नहीं कराया, तो उनका गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि eKYC की जरूरत सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को है, जिनका वेरिफिकेशन अब तक नहीं हुआ है। सरकार ने कहा कि यह कोई नया नियम नहीं है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जो जानकारी दी है, वह पुराने अभियान का ही हिस्सा है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि ज्यादा से ज्यादा गैस ग्राहक अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लें, ताकि सिस्टम में फर्जीवाड़ा न हो। ग्राहकों को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय

ने बताया कि eKYC की प्रक्रिया घर बैठे आसानी से और मुफ्त में पूरी की जा सकती है। ग्राहक संबंधित गैस कंपनी के मोबाइल एप के जरिए इसे खुद ही पूरा कर सकते हैं। eKYC के लिए सिर्फ 'आधार कार्ड' और 'रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर' की ही आवश्यकता होती है। कानून कहता है कि e-KYC सिर्फ उनके लिए जरूरी है जो 'उज्ज्वला' या 'पहल' स्कीम के तहत सब्सिडी लेते हैं।

किसे करानी होगी ई-केवाईसी और किसे नहीं?

यदि आप एक सामान्य एलपीजी ग्राहक हैं और आपने पहले अपना eKYC करवा लिया है, तो आपको यह प्रक्रिया दोबारा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह नियम सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जिनका रिकॉर्ड अब तक अपडेट नहीं हुआ है। उज्ज्वला योजना के ग्राहकों के लिए नियम थोड़े अलग है। इन ग्राहकों को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होता है। यह वेरिफिकेशन भी सिर्फ उन उज्ज्वला ग्राहकों के लिए आवश्यक है।

असल में कानून क्या कहता है?

सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के मुताबिक, सरकार सिर्फ उन्हीं सेवाओं या फायदों के लिए आधार अनिवार्य कर सकती है, जहां पैसा सीधे सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा हो। गैस कनेक्शन अपने आप में कोई सब्सिडी नहीं है। कोई भी बाजार भाव पर कनेक्शन ले सकता है और करोड़ों लोग बिना किसी सरकारी मदद के पूरी कीमत चुकाकर गैस खरीदते हैं। ऐसे लोगों के लिए आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

सरकार का कहना है कि ई-केवाईसी कराने का मुख्य उद्देश्य सिस्टम में पारदर्शिता लाना है। इससे 'घोस्ट कंज्यूमर्स' यानी उन फर्जी गैस कनेक्शनों को हटाने में मदद मिलती है जो किसी और के नाम पर चल रहे हैं। इसके अलावा इससे एलपीजी की कालाबाजारी रोकने में भी मदद मिलेगी।

चांदी ₹5 हजार बढ़कर ₹2.54 लाख पर पहुंची

नई दिल्ली। सोने और चांदी के दामों में आज यानी 17 मार्च को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 300 रुपए बढ़कर 1.56 लाख रुपए पर पहुंच गया है। एक किलो चांदी 5 हजार रुपए बढ़कर 2.54 लाख रुपए पर पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, 29 जनवरी को सोने की कीमत 1.76 लाख रुपए और चांदी के दाम 3.86 लाख रुपए के ऑलटाइम हाई पर पहुंच गई थे। इसके बाद से इनकी कीमत में काफी गिरावट आ चुकी है। इसलिए इनकी खरीदारी देखने को मिल रही है। यानी इसकी कीमत इस साल अब तक 23 हजार बढ़ चुकी है। वहीं चांदी भी इस दौरान 24 हजार रुपए महंगी हुई है। एक्सपर्ट्स के इनुसार रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद सोना फिलहाल 'करेक्शन फेज' (कीमतों में सुधार) में है। शॉर्ट टर्म में मोमेंटम थोड़ा कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तेजी का रुझान बरकरार है।

लग्जरी गाड़ी से घूमकर रेकी करते, शॉप के शटर तोड़कर हैंडसेट चुराते

लखनऊ से मोबाइल चुराकर नेपाल में बेचने वाले 4 गिरफ्तार

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ से मोबाइल चुराकर नेपाल में बेचने वाले चोर गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 41 मोबाइल फोन, 2 टैबलेट, अवैध हथियार और वारदात में इस्तेमाल लग्जरी कार और बाइक बरामद की गई। मोबाइलों की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। एडीसीपी नॉर्थ रिषभ रूणवाल ने बताया- 22 फरवरी को जानकीपुरम गार्डन निवासी अभिषेक चौधरी ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। चोर करीब 30 नए मोबाइल, 10 पुराने मोबाइल, 4 टैबलेट और 10 हजार रुपए नकद ले गए थे। पुलिस मड़ियांव थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर

आरोपियों की तलाश में लगी थी। बरामद सामान का संबंध मड़ियांव समेत अलीगंज, जानकीपुरम, चिनहट और इटौंजा थानों में दर्ज कई चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है। उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य जिलों से भी जुटाई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे लखनऊ के विभिन्न इलाकों से मोबाइल चोरी कर उन्हें नेपाल में ऊंचे दामों पर बेचते थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि बरामद सामान का संबंध मड़ियांव के अलावा अलीगंज, जानकीपुरम, चिनहट और इटौंजा थानों में दर्ज कई चोरी की घटनाओं से भी है।पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है और उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य जिलों से भी जुटाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा।फिलहाल, इस कार्रवाई को राजधानी में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

■ आरोपियों के पास से 41 मोबाइल, 2 टैबलेट के अलावा 2 अवैध देशी तमंचे (.303 बोर), 1 रिवॉल्वर (.32 बोर) और कुल 9 जिंदा कारतूस बरामद हुए।

बहराइच के रहने वाले आरोपी

मुखबिर की सूचना पर मंगलवार सुबह मड़ियांव के यादव चौराहे के पास लोखड़िया मोड़ सर्विस रोड से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अमन (23), जीशान (26), अजमत अली उर्फ मंटू (25) और समीर उर्फ डाबर (19) के रूप में हुई है। सभी लखनऊ और बहराइच के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से 41 मोबाइल, 2 टैबलेट के अलावा 2 अवैध देशी तमंचे (.303 बोर), 1 रिवॉल्वर (.32 बोर) और कुल 9 जिंदा कारतूस बरामद हुए।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पहले बाइक और कार से इलाके की रेकी करते थे। इसके बाद बंद दुकानों का शटर और ताला तोड़कर मोबाइल व टैबलेट चोरी कर लेते थे। चोरी का सामान नेपाल ले जाकर बेच देते थे और रुपए आपस में बांट लेते थे। आरोपी चोरी के दौरान हथियार साथ रखते थे।

राम मनोहर लोहिया संस्थान की इमरजेंसी में मरीज की मौत पर बवाल

डॉक्टरों-कर्मचारियों से मारपीट, तीन हिरासत में

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। राजधानी के राम मनोहर लोहिया संस्थान में मंगलवार को इमरजेंसी के ट्रायज एरिया में भर्ती एक मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित तीमारदारों ने डॉक्टरों और कर्मचारियों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए न सिर्फ हंगामा किया, बल्कि मारपीट और तोड़फोड़ भी की, जिससे कुछ समय के लिए अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो गईं।घटना से पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार, मरीज लाल बहादुर (45) को गंभीर हालत में इमरजेंसी में लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरीज की मौत से आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध

शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और तीमारदारों ने डॉक्टरों व स्टाफ के साथ मारपीट कर दी। हंगामे के दौरान इमरजेंसी क्षेत्र में तोड़फोड़ भी की गई, जिससे अस्पताल की व्यवस्था कुछ समय के लिए पूरी तरह प्रभावित हो गई। इस वजह से अन्य मरीजों के इलाज पर भी असर पड़ा और काफी देर तक चिकित्सा सेवाएं बाधित रहीं। अस्पताल प्रशासन ने किसी तरह स्थिति को संभालने की कोशिश की और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची ने मौके पर पहुंच कर हालात को नियंत्रित किया।अस्पताल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। परिजनों द्वारा लगाए गए इलाज में कोताही के आरोपों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

फास्ट न्यूज

'परिवार के सदस्य को नौकरी-50 लाख सहायता मिले'

मोहनलालगंज। मोहनलालगंज इलाके के कनकहा गांव निवासी ग्राम रोजगार सेवक रमेश प्रजापति ने 15 मार्च को रायबरेली में आत्महत्या कर ली थी। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उसके परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढांढ़स बंधाया। परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया।

पीएनजी पाइप फटने से हुआ गैस रिसाव, हड़कंप

कानपुर। बर्रा में जेसीबी से सीवर लाइन की खोदाई के दौरान पीएनजी पाइप लाइन फटने से अफरा-तफरी मच गई। तेजी से गैस रिसाव होने पर आनन-फानन में इलाकाई लोगों ने पुलिस और मेंटीनेंस कर्मियों को सूचना दी। मौके पर पहुंची मेंटीनेंस टीम को लीकेज की मरम्मत करने में करीब 2 घंटे से भी अधिक का समय लगा। बेसमेंट की खोदाई के दौरान जेसीबी की चपेट में आकर गिरे पेड़ और बिजली के खंभों के बीच में फंसकर सैलून कारीगर की मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों ने यूपी-112 और पीएनजी के टोल फ्री नंबर पर घटना की सूचना दी। सीयूजीएल के वरिष्ठ प्रबंधक माही खान ने बताया- दोपहर करीब 1:40 बजे लीकेज की सूचना मिली थी। इसके बाद तुरंत मेंटेनेंस टीम को मौके पर भेजा गया। करीब 2 घंटे में लीकेज को ठीक कर लिया गया। शाम करीब 4 बजे गैस सप्लाई सामान्य कर दी गई।

यूपी में अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखनी होगी

लखनऊ। यूपी सरकार ने लोगों की सेहत से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल, 2026 से प्रदेश में अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखना होगा। इस नियम के लागू होने के बाद दुकानदार अब ताजा अंडा कहकर पुराने या खराब अंडे बेच नहीं पाएंगे। पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की जांच में सामने आया कि कई जगहों पर पुराने या खराब अंडे 'फ्रेश' बताकर बेचे जा रहे थे।

परिवहन, जलकर समस्या को लेकर वित्त मंत्री से मिले बंसल

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। परिवहन व्यवसायियों के ऊपर लागू की गई योजना से संबंधित कुछ बिंदुओं पर हो रही कठिनाई तथा जल कनेक्शन के बिना आ रहे लाखों रुपयों के बिल के विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से संदीप बंसल के नेतृत्व में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल मिला। बंसल ने कहा कि सरकार ने नए परिवहन व्यवसायियों के लिए एकमुश्त कर जमा कराने की जो योजना बनाई है, स्वागत योग्य है परन्तु जो पुराने परिवहन व्यवसायी हैं या जिनके पास एक अथवा दो गाड़ी हैं उनके लिए एक मुश्त पैसा जमा कराना अव्यवहारिक नहीं हो पा रहा है, उनको पुरानी व्यवस्था अथवा तिमाही कर जमा कराने की छूट प्रदान की जाए। संदीप बंसल ने ये भी बताया कि बिना पानी के कनेक्शन के लाखों रुपये के बिल लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में नगर निगमों नगरपालिकाओं द्वारा भेजे गए हैं जिनको भुगतान किया जाना व्यापारी समाज के लिए संभव नहीं है। इस नियम में परिवर्तन करते हुए व्यापारियों को

राहत प्रदान की जाए। तथा अनावश्यक उत्पीड़न से बचाया जाए। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने विषय की गंभीरता को समझते हुए तत्काल नगर विकास मंत्री एवं परिवहन मंत्री से वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रयास करके इन विषयों का समाधान कराया जाएगा। खन्ना के साथ वार्ता करने वाले प्रतिनिधिमंडल में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल लखनऊ महानगर के अध्यक्ष सुरेश छाबलानी, महामंत्री अनुज गौतम, उत्तर प्रदेश परिवहन व्यवसायी संघ के अध्यक्ष पीयूष गुप्ता प्रमुख रूप से शामिल थे।

अंडे को लेकर 1 अप्रैल से जारी होंगे सख्त नियम

प्रत्येक अंडे पर लिखनी होगी एक्सपायरी डेट, ताजा बताकर खराब अंडे बेच नहीं पाएंगे दुकानदार

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। यूपी सरकार ने लोगों की सेहत से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल, 2026 से प्रदेश में अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखना होगा। इस नियम के लागू होने के बाद दुकानदार अब ताजा अंडा कहकर पुराने या खराब अंडे बेच नहीं पाएंगे। ग्राहक खुद तारीख देखकर फैसला ले पाएंगे कि अंडा सुरक्षित है या नहीं। पशुपालन और डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने कहा, सरकार ने उपभोक्ताओं की सेहत की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया है। यह कदम खाद्य पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरिशंकर सिंह ने बताया, 18 मार्च को प्रदेश के प्रमुख अंडा डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक बैठक बुलाई है। इसमें शासनादेश को समझने और लागू करने के लिए उनसे चर्चा होगी। 1 अप्रैल से ये लागू होना है, हम समझना चाहते हैं कि इसे कैसे लागू किया जाए और कैसे इसकी निगरानी की जाएगी।

"एफएसडीए के जॉइंट कमिश्नर हरिशंकर सिंह ने बताया, दो साल से इसकी कवायद चल रही थी। पहले बैच नंबर लिखने का निर्णय हुआ, लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं था। क्योंकि अंडे अलग-अलग जगह आते हैं, ऐसे में बैच नंबर लिखना संभव नहीं था। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि अंडे पर डेट लिखा जाए। इसके लिए अंडों पर लेइंग और एक्सपायरी डेट को मुहर से अंकित किया जाएगा।"

क्यों लाया गया यह नियम?

पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की जांच में सामने आया कि कई जगहों पर पुराने या खराब अंडे 'फ्रेश' बताकर बेचे जा रहे थे, जिससे लोगों की सेहत को खतरा हो सकता था। नियमों का पालन नहीं हो रहा था।

कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जा सकता। दोनों को अलग-अलग तापमान और परिस्थितियों की जरूरत होती है। सही स्टोरेज से अंडों की ताजगी लंबे समय तक बनी रहती है। फिलहाल, राज्य में अंडों के लिए सिर्फ दो विशेष कोल्ड स्टोरेज हैं। एक आगरा में और दूसरा झांसी में। पूरे राज्य के लिए यह संख्या बहुत कम है। स्टोरेज की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है। सरकार को भविष्य में और कोल्ड स्टोरेज बनाने की जरूरत होगी ताकि नए नियम आसानी से लागू हो सकें।

अंडे पर क्या-क्या छपा होगा?

लेइंग डेट: मुर्गी ने अंडा कब दिया यानी उत्पादन तारीख।

एक्सपायरी डेट: अंडा कब तक सुरक्षित रहेगा यानी खराब होने की तारीख।

अभी क्या था नियम: अंडे की ट्रे पर उत्पादन तिथि लिखी जाती है, लेकिन हर अंडे पर व्यक्तिगत स्टैंपिंग नहीं।

नियम तोड़ने पर सजा क्या?

अगर कोई उत्पादक, किसान, पोल्ट्री फार्म या दुकानदार इस नियम का पालन नहीं करता, तो सख्त कार्रवाई होगी। उनके अंडों को जब्त कर नष्ट किया जाएगा या उन पर 'मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त' की मुहर लगा दी जाएगी। ऐसे अंडे बाजार में नहीं बिक सकेंगे। नियम मानने के लिए सभी को मजबूर किया जाएगा। सामान्य कमरे के तापमान (लगभग 25 से 35 डिग्री सेल्सियस) पर अंडा 2 हफ्ते तक सुरक्षित रहता है।

बच्ची की हत्या, न्यूड लाश खेत में दफनाई

पड़ोसी पर रेप के बाद वारदात का शक

■ पुलिस ने आरोपी पड़ोसी के घर से मिट्टी में सने कपड़े बरामद किए हैं। फोरेंसिक टीम ने इसकी जांच शुरू कर दी है।

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर। कानपुर में 11 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह उसका शव एक खेत में गड़ा हुआ मिला। शव पर कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं था। चोट के गहरे निशान थे। आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद बच्ची का मर्डर किया गया। परिवार वालों ने पड़ोसी पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उसका घर फूंकने की कोशिश की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। भीड़ को तितर-बितर

किया। गुस्साए लोगों को शांत कराया। आरोपी के घर को घेरकर जांच शुरू की। पड़ताल के दौरान पुलिस को आरोपी पड़ोसी के घर से मिट्टी से सने कपड़े टंगे मिले। फोरेंसिक टीम ने इसे कब्जे में ले लिया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, बच्ची के पिता मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। बच्ची 5 बहनों में तीसरे नंबर पर थी।

चिकन बिरयानी परोसी, हिंदू संगठन बोले- हड्डियां नदी में फेंकीं, 14 गिरफ्तार

गंगा में नाव पर इफ्तार पार्टी

कार्यवाई

तमसा संकेत, एजेंसी

वाराणसी। काशी में गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी की गई। सोमवार को हुई इस पार्टी में आयोजकों ने रोजेदारों को फल और मेवे के साथ चिकन बिरयानी भी परोसी। साथ ही इफ्तार पार्टी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जल्द ही वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने लगा। वीडियो में चिकन बिरयानी की बात सामने आते ही भाजपा और हिंदूवादी संगठन भड़क गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसके 8 घंटे के भीतर पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। काशी में

गंगा नदी पर सोमवार शाम एक युवक ने रोजा इफ्तार का कार्यक्रम रखा। उसने रोजेदारों को गंगा घाट पर बुलाया। यहां एक बड़ी नाव पहले से बुक की गई थी। इसके बाद सभी लोग अस्सी घाट से नमो घाट तक नाव से गए। वहां नाव पर मौजूद रोजेदारों ने पहले नमाज पढ़ी। फिर खजूर और फल खाकर रोजा खोला। एक अन्य वीडियो में नाव पर बैठे लोग बड़े भगोने से कुछ निकालकर खाते दिखे। भाजयुमो महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने चिकन बिरयानी खाई। साथ ही उसकी हड्डियां गंगा में फेंक दीं। इस मामले को लेकर कोतवाली में लिखित शिकायत दी। उन्होंने कहा- मां गंगा सनातन धर्म अनुयायियों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। मां गंगा के जल का आचमन करने के लिए देश-विदेश से रोज लाखों श्रद्धालु आते हैं। गंगा की धारा में नाव पर बैठकर इफ्तार के समय चिकन बिरयानी खाना और उसके अवशेष गंगा में फेंकना निंदनीय है।

शिकायत के साथ पुलिस को घटना का वीडियो भी साक्ष्य के रूप में दिया है। रजत जायसवाल ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई और वीडियो को साक्ष्य के रूप में पुलिस को सौंपा। उन्होंने कहा कि मां गंगा सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र हैं और यहां इस प्रकार की गतिविधियां निंदनीय हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु गंगा जल का आचमन करने आते हैं, ऐसे में इस तरह की घटना भावनाओं को आहत करने वाली है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और महज 8 घंटे के भीतर 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल, यह मामला धार्मिक भावनाओं और आस्था से जुड़ने के कारण चर्चा में बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से बचें और शांति व्यवस्था बनाए रखें।

"रजत जायसवाल ने कहा कि इससे सनातन अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ऐसे काम से मुस्लिम समुदाय के युवाओं में जानबूझकर जिहादी मानसिकता बढ़ रही है। उन्होंने नाव चालक के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। साथ ही उस-का लाइसेंस निरस्त करने की भी मांग की।

■ वाराणसी पुलिस ने 8 घंटे में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है।

पृष्ठ 01 का शेष...

'उद्योग' की...

बेंच में जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस जॉयमाल्या बागची, जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी को तय किया था कि 'उद्योग' की परिभाषा, सरकारी संस्थाओं की स्थिति, NGO और चैरिटी संस्थाओं की भूमिका तथा 1978 के पुराने फैसले की समीक्षा जैसे मुद्दों पर यह बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। इस मामले के फैसले से यह तय होगा कि किन-किन संस्थाओं पर श्रम कानून लागू होंगे। इससे कर्मचारियों के अधिकार जैसे छंटनी, वेतन, यूनियन बनाने का अधिकार और सेवा शर्तों पर भी असर पड़ सकता है। 1978 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर ने 'बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड' मामले (1978) में उद्योग की विस्तृत परिभाषा दी थी। फैसले के पैराग्राफ 140 से 144 में कहा गया था कि जहां नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध है और कोई सेवा/काम होता है, वह उद्योग हो सकता है। इस परिभाषा की वजह से सरकारी विभाग, अस्पताल, स्कूल, NGO भी उद्योग माने जाने लगे और उन पर लेबर कानून लागू हो गए। मई 2005 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(j) में उद्योग शब्द की परिभाषा की व्याख्या से जुड़े इस मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया था। बेंच ने कहा था कि बड़ी बेंच को सभी कानूनी सवालों के हर पहलू और गहराई पर विचार करना होगा। इसके बाद 2017 में तत्कालीन CJI टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने कहा था कि उसकी राय में, उसके सामने आई अपीलों को नौ जजों की बेंच के सामने रखा जाना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे के गंभीर और दूरगामी असर हो सकते हैं।

यूपी में फिर...

इसके अलावा बांदा में पारा 37.4C, हमीरपुर में 36.2C, उरई में 36C और झांसी में 36C रिकॉर्ड किया गया। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने मौसम में हुए बदलाव की वजह बताई। उन्होंने कहा- 15 और 16 मार्च को पूरे प्रदेश में हल्की बारिश हुई। आज और कल मौसम साफ रहेगा। 19 मार्च से प्रदेश में एक और विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इस वजह से बारिश-आंधी का दौर फिर से शुरू होगा। 40-50 किमी की स्पीड से हवा चलेगी। ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 18 मार्च तक प्रदेश में कोई भी मौसमी सिस्टम एक्टिव नहीं रहेगा। इस वजह से मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। इस वजह से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी हो सकती है। 19 मार्च से एक नया सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करेगा। इसके असर से पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश होगी। जो धीरे-धीरे पूरे प्रदेश को अपनी जद में ले लेगी। 22 मार्च तक कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बारिश का सीधा असर तापमान पर भी पड़ेगा। अधिकतम तापमान में लगभग 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की तेजी से गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे पहुंच सकता है।कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि आगामी बारिश और आंधी-तूफान की संभावना को देखते हुए खेतों में खड़ी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

दावा : यूएई के ...

टस्क ने कहा कि पोलैंड की सरकार ईरान में किसी भी सैन्य अभियान में शामिल होने की योजना नहीं बना रही है और इस मुद्दे पर सहयोगी देशों के बीच भी कोई भ्रम नहीं है। टस्क ने यह भी कहा कि पोलैंड फिलहाल अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है, खासकर यूक्रेन सीमा पर चल रहे तनाव के मद्देनजर। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सहयोगी देशों से होर्मुज स्ट्रेट में टैंकरों की सुरक्षा के लिए सैन्य मदद मांगी है।

लोकसभा से 8...

उन्होंने कहा कि खासकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे इसका ख्याल रखें। इसके बाद सदन में सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से कहा,'प्लेकार्ट और एआई से बनाई गई तस्वीरें प्रदर्शित न करें।' संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और कांग्रेस सांसद कोडिकुन्निल सुरेश, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 15वीं रिपोर्ट के समर्थन में एक प्रस्ताव पेश करेंगे; यह रिपोर्ट 16 मार्च को प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा 2026-27 के लिए अनुदान मांगों पर होने वाला मतदान भी होगा। तीन मंत्रालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा: रेल मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, और गृह मंत्रालय। संसदीय स्थायी समितियां अपनी महत्वपूर्ण रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगी। इनमें कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और भाजपा सांसद विष्णु दयाल राम, गृह मामलों की समिति की रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगे; इन रिपोर्टों में अनुदान मांगों (2025-26) के संबंध में पिछली सिफारिशों पर सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई का विवरण शामिल होगा। राहुल गांधी ने लोकसभा में गुरुवार को LPG संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, 'किसी भी देश की बुनियाद उसकी ऊर्जा सुरक्षा होती है। अगर अमेरिका यह तय करे कि हम रूस से गैस या तेल खरीद सकते हैं या नहीं, तो यह समझ से परे है।

एचपी अफसरों के हत्यारोपी की मार्केट पर चला बुलडोजर

बदायूं में 11 दुकानें ढहाईं, 53 खाली कराई गई

तमसा संकेत, एजेंसी

बदायूं। बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HP) के 2 अफसरों के हत्यारोपी अजय सिंह की मार्केट पर बुलडोजर चला। मंगलवार सुबह 10 बजे SDM धर्मेंद्र सिंह 2 बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू हुई। पहले से चिह्नित 11 दुकानें और एक हॉल ढहा दिया गया। 53 अन्य खाली कराई गईं, इन पर आगे कार्रवाई होगी। पुलिस और PAC के 100 से ज्यादा जवान तैनात रहे। बैरिकेडिंग कर किसी के आने-जाने पर रोक लगा दी गई थी। प्रशासन का कहना है कि मार्केट सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। आरोपी ने फर्जी कागजों के जरिए इसे खुद, अपने ताऊ और रिश्तेदारों के नाम करवा लिया था। ज्यादातर दुकानें किराए पर उठी थीं। हर महीने 1 लाख से ज्यादा किराया आता था। 2 दिन पहले नोटिस दिया गया था। अजय सिंह ने 12 मार्च को HPCL प्लांट में घुसकर DGM सुधीर गुप्ता (55) और

असिस्टेंट मैनेजर हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद पुलिस ने अजय को दोनों पैर में गोली मारकर पकड़ा था। वहीं, इस मामले में लापरवाही करने पर दातागंज CO केके तिवारी को भी हटा दिया गया था। अजय ने पुलिस पूछताछ में बताया था- 12 मार्च को दोपहर 1 बजे मैं HPCL प्लांट गया था। उस वक्त प्रशासनिक भवन में मीटिंग चल रही थी। मैं वहां पहुंचा, तो 5 लोग बैठे थे। मैंने सभी को बातों में उलझाए रखा कि मुझे नौकरी पर वापस रख लो।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676